

3. The amount of pension is Rs. 50 per mensem, and is payable either to a freedom fighter or his widow or minor children whose annual income from all sources including help from near relatives does not exceed Rs. 300 per mensem. The pension is payable during the life-time of the freedom fighter and in the case of his widow for her life time or till re-marriage.

4. An Advisory Committee will be constituted in each district consisting of old freedom fighters who command respect among the people, preferably those who had participated in the 1930 or 1942 movements, and in Malabar in the 1938 Movement in Travancore etc.

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद

*73. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक पहाड़ी विकास परिषद कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों के विकास हेतु उक्त परिषद् द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त परिषद् द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान किये जाने वाले कार्य का पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन भारद्वाज) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) बोर्ड पहाड़ी जिलों के लिए योजनायें बनाता रहिगा तथा राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसकी कार्यमिति पर भी नजर रहेगा ।

विचारण

अब तक, पुनर्गठित बोर्ड की मीटिंग दो बार हुई है—अक्टूबर, 1969 में तथा दिसम्बर,

1970 में। अब तक बोर्ड ने जो कार्य किया है वह इस प्रकार है :—

(1) वार्षिक योजना 1970-71 पर विचार किया तथा विभिन्न विकास खण्डों के लिये परिव्ययों की सिफारिश की ।

(2) पर्वतीय जिलों के पारस्परिक पिछड़े-पन का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने तथा 1970-71 में अनेको पर्वतीय जिलों में एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का वितरण करने की सिफारिश करने का निर्णय किया है ।

(3) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये संस्थागत वित्त प्राप्त हेतु एक विकास निगम की स्थापना करने की सिफारिश की। अब यह निगम स्थापित किया जा चुका है। इसका मुख्यालय नैनीताल में है ।

(4) पर्वतीय जिलों में विकास की आवश्यकताओं पर विचार करने तथा उनकी जांच करने और राज्य सरकार द्वारा हाथ हाथ में लिये जाने वाले कार्यक्रमों तथा उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करने और उसी साहस्य पर पर्वतीय विकास की योजना भी बनाने के लिये एक योजना उप-समिति का गठन किया। तदनुसार 29-3-1971 को राज्य सरकार द्वारा एक उप-समिति का गठन किया गया जिसमें सभी संसद-सदस्य, जिला परिषदों के अध्यक्ष (आजकल जिलाधीश जो कि जिला परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं) तथा पर्वतीय जिलों के आयुक्त और 8 पर्वतीय जिलों में से प्रत्येक का एक-विधायक समाविष्ट था ।

(5) पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया।

(6) पर्वतीय जिलों की वार्षिक योजना 1971-72 पर विचार किया।

Anti-Indian Propaganda over Pakistan Radio

*74. SHRI R. S. PANDEY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHNA AND PRASARAN MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Pakistan has increased its anti-Indian propaganda over the Pakistan Radio recently in the wake of freedom struggle in East Pakistan ; and

(b) if so, the steps taken by Government to counter this Pakistan Propaganda ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) Yes, Sir.

(b) Correct facts are being presented in the news bulletins and commentary programmes of All India Radio both in its home and external services. The number of such programmes has also been increased.

Settlement of Assam-Nagaland Boundary Dispute

*75. SHRI SAROJ MUKHERJEE : Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Assam Finance Minister on the 19th March, 1971 in the Assembly about the Central Government's failure to settle the Assam-Nagaland boundary dispute ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by the Government to resolve this dispute ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). Government have seen the statement. The

Finance Minister of Assam reiterated the stand of the State Government in this dispute and expressed the hope that the Central Government would take steps to resolve the issue within a reasonable time.

(c) The matter is receiving the active attention of the Government.

Sub-Standard Quality of Coir Goods Exported to U.S.S.R.

*76. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the U.S.S.R. authorities have recently protested against the sub-standard quality of coir goods exported from India ;

(b) whether any inquiry has been held into the matter and, if so, the result thereof; and

(c) the amount of compensation, if any, which the U.S.S.R. authorities have claimed in lieu of their losses ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRALAYA MEN UP-MANTRI) (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

Kindly refer to the statement attached.

Statement

The inquiry revealed that :—

(i) The following exporters shipped consignments of coir matting and rugs to USSR :

1. Vaikath Bros. Alleppey.
2. Gopal Coir Factory, Alleppey.
3. The Kerala State Coir Corporation, Alleppey.
4. The Indian Manufacturing Co., Alleppey.
5. The Travancore Mats and Matting Coop. Society, Ltd., Alleppey.
6. Alleppey Coir Mats and Matting Cooperative Society Ltd., Alleppey.